

Relics of Lord Buddha at Piprahwa and Ganwaria

2474. SHRI B. C. KAMBLE: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether relics of Lord Buddha and also remains of ancient Kapilvastu city were brought to light at Piprahwa-Ganwaria villages in District of Basti in Uttar Pradesh and Government of India started the work of excavations there;

(b) whether the excavation work is stopped and there have been encroachment at the said places; and

(c) what steps Government propose to take to stop the encroachments and resume further excavations?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) The excavations at Piprahwa and Ganwaria, District Basti in U.P. have brought forth Buddhist structural remains and two unincised relic caskets at the lowest level of the stupa which had yielded one inscribed casket in 1898. A large number of sealings from a monastery at Piprahwa mentioning *Kapilvastu* in Brahmi characters of first-second century A.D. point to the possibility of the existence of ancient Kapilvastu thereabout.

(b) Excavation work now remains suspended due to non-field season. The site is free from encroachment.

(c) The Survey has already taken steps to acquire such areas as are considered necessary. Only after a detailed study of the present finds, it would be possible for the Survey to decide whether further excavations are needed at the site.

लाख की खेती

2475. श्री कड़िया मुण्डा : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में लाख की खेती कितने क्षेत्र में होती है ;

(ख) पूरे देश में लाख का कितना उत्पादन होता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार लाख की खेती को बढ़ावा देने का है और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजना है; और

(घ) बिहार में, विशेषकर रांची जिले में, लाख का कुल कितना उत्पादन होता है ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लाख पोषक पेड़ों के बाग नहीं लगाये जाते हैं। अतः लाख की खेती के क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (घ). पाँचवी योजना के प्रथम तीन वर्षों के संबंध में देश में स्टिक लाख का उत्पादन नीचे दिया गया है जिसमें बिहार

क्या रांची जिलों के बारे में भी जानकारी दी गई है :— (माता कीटरी टनों में)

वर्ष	अखिल भारतीय उत्पादन	बिहार में उत्पादन	रांची में उत्पादन
1974-75	24,690	14,525	5,774
1975-76	21,767	12,853	7,066
1976-77	23,869	15,559	7,846

(ग) जी हां। बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लाख के विकास के लिये भारत सरकार ने, पांचवी योजना की अवधि के दौरान, 9.00 लाख रुपये की लागत की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना मंजूर की है। इसमें (1) लाख के उत्पादकों को लाख-पूर का मुफ्त संभरण (2) काट-छाट के उपकरणों की निःशुल्क सप्लाई, पैकेज खण्डों में लाख की खेती की उन्नत पद्धतियों के प्रदर्शन और कुछ लाख के फार्मों में रख-रखाव का प्रावधान है।

Translation of Nepali Books

2476. SHRI K. B. CHETTRI: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) the number of inter-language translation of Nepali books after the recognition of Nepali language by Sahitya Academi;

(b) whether Government have selected any qualitative book for award to the best authors; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (DR. PRATAP CHANDRA CHUNDER): (a) Inter-language translation of Nepali books is still to be taken up by the Sahitya Akademi.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

अन्तर्राष्ट्रीय खेल के रूप में कबड्डी का खेल

2477. श्री जगवन्धी प्रसाद यादव : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में राष्ट्रीय खेल कबड्डी को शामिल करने का प्रयास करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : (क) और (ख) : अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में 'कबड्डी' को एक खेल के रूप में स्वीकार करना, अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति, एशियाई खेल फेडरेशन, कामनवैल्य खेल फेडरेशन आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय खेल निकायों का काम है, बशर्ते कि इन निकायों द्वारा निर्धारित शर्तें पूरी होती हो। भारतीय ओलम्पिक एसोसिएशन ने कबड्डी को अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में शामिल कराने के लिये प्रयत्न करने का आश्वासन दिया है। यह मामला सरकार के हाथ में नहीं है।